CORRECTION OF ANSWER TO USQ 4591 RE RELIGIOUS INTOLERANCE IN BOMBAY SCHOOL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN):

In reply to part (b) of Unstarred Question No. 4591 by Shri Madhu Limaye, Shri A. B. Vajpayee, Shri Rabi Ray, Shri George Fernandes and Shri Abdul Ghani Dar in the Sabha on 5-7-1967, my predecessor, Shri Bhagwat Jha Azad had given a negative reply implying that no teacher had been suspended for protesting in that case. On further enquiry, it has now been reported by the State Government that one teacher had been suspended; and the reply should therefore, be in the affirmative. I regret the inconvenience to the House.

12.28 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Letter reported to have been written by Director General of Technical Development to M|s. Asian Cables Ltd. Bombay

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittor): Sir, I Call the attention of the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"Letter reported to have been written by Shri B. D. Kalelkar, Director-General of Technical Development to the General Manager of M/s. Asian Cables Limited, Bombay on 15-3-69 demanding Rs. 4 lakhs for the issue of diversification permission to manufacture polythene pipes."

श्री शशि भूषण (खारगोन) : आन ए पायंट आफ आर्डर । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस आफिसर का उन्होंने जिक्र किया है, उस गुप्ता के खिलाफ कोई सी बी आई की एनक्वायरी चल रही है या नहीं । वह उन के रिश्तेदार भी हैं । (व्यवधान) मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जिस अफसर ने यह लैटर फोर्ज किया है, क्या उसके खिलाफ सी बी आई की एनक्वायरी चल रही है या नहीं । (व्यवधान)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय,यह प्रवचन क्यों दे रहे हैं ? मेरे दो व्यवस्था के प्रश्न हैं । (व्यवधान)

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : इस मामले के बैकग्राउंड में जो बातें हैं, उन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए । बताया जाता है कि वह गुप्ता के कुछ अजीज होते हैं । (व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है । मैं किसी को नहीं जानता हूं । यह बिलकुल झूठ बात है । (व्यवधान) और मैं चाहता हूं कि इस में एनक्वायरी हो जानी चाहिए कि वह मेरा रिश्तेदार है या नहीं । इस की एन्क्वायरी आप कर लें और होम मिनिस्टर कर लें, अगर मेरा रिश्तेदार निकले तो मुझे सजा मिलनी चाहिए और नहीं तो इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए । मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर एन्क्वायरी करें ।.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सब शांत रहिए । सभी बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है । श्री मधु लिमये किस बात पर बोल रहे हैं ? प्वाइंट आफ आर्डर किस बात पर उठा रहे हैं? Reply has not yet come. Let the reply come from the Minister.

श्री मधु लिमये : यह पहले आना चाहिए, इसी मजमून के बारे में है । पहले मुझे सुन लीजिए, फिर रोशनी पड़ेगी ।

श्री शशि भूषण : मैं पहले प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहा था तो नहीं रेज करने दिया । यह कैसे रेज कर रहे हैं ?... (व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त : यह पक्के रिश्वत खाने वालों के एजेंट हैं.... (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न पहले सुन लें फिर मंत्री महोदय बोलें।

SHRI SITARAM KESRI (Katihar): The reply has to come from the Minister. Then it can be discussed.

श्री मधु लिमये : प्रिलिमिनरी प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है। ग्राप क्या बात कर रहे हैं?

ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे दो व्यवस्था के प्रश्न हैं। पहला मेरा यह प्रश्न है कि मैंने ग्रपना ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव प्रधान मंत्री को सम्बोधित करके दिया था। तो इस का जवाब प्रधान मंत्री क्यों नहीं दे रही हैं? इसका जवाब ग्रौद्योगिक विकास मंत्री क्यों दे रहे हैं? जिनके मंत्रालय के उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार का मामला है? पहला मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है ग्राप इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बात का निर्णय दीजिए कि जब मैंने प्रधान मंत्री से निवेदन किया था, विनती की थी कि वह जवाब दें तो यह जवाब क्यों दे रहे हैं?

दूसरा व्यवस्था का प्रश्न ग्रध्यक्ष महोदय, यह है कि मैंने जो ध्यान ग्राकर्षण का नोटिस दिया था उस में से मैं देख रहा हूं कि कुछ हिस्सा हटा दिया गया है। जब कई नोटिसेज ग्रा जाती हैं तो दफ्तर हमेशा यह करता है, यह सिलसिला रहा है कि एक काम्प्रीहेंसिव कालिंग ग्रटेंशन वह बना देते हैं। तो इस वक्त वह क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसमें केवल एक ही सवाल ग्राया—

The issue of diversification permission to manufacture polythene pipes.

मैंने जो दिया था उस में था :

Illegal loaning and selling of raw, materials imported against users' license. (*Interruptions*).

एक प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर चल रहा है, उस पर यह कैसे बोलने लग गए?

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : यह ग्राप इस में क्यों लाना चाहते हैं......

श्री मधु लिमये : बूटा सिंह जी, ग्राप हमारे मित्र हैं, लेकिन बीच में दखल मत दीजिए।

मुझे दूसरा निवेदन यह करना है कि लोक सभा सचिवालय का हमेशा यह दस्तूर रहा है कि एक विषय के बारे में एक से ग्रधिक नोटिसेज ग्राती हैं तो एक ही विषय को 'ग्रगर' है तो वह सब को मिला कर एक काम्प्रीहेंसिव बनाकर दे देते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ ग्रनवधानता से हुग्रा हो, इनऐडवर्टेंस से हुग्रा हो। लेकिन मेरे मुद्दे यह थे :

Illegal loaning and selling of raw materials imported against users' license.

केवल डाइवर्सिफिकेशन का नहीं था। एशियन केबल्स के बारे में ही मेरा एक ग्रारोप नहीं था। मेरे तीन ग्रारोप थे। एक ग्रारोप था कि यूज लाइसेंस को ले कर उन्होंने जो कच्चा माल बनवाया वह उन्होंने नियमों को तोड़ कर किया ग्रौर दूसरा ग्रारोप मेरा था कि यूजर लाइसेंस के खिलाफ जो उन्होंने माल मंगवाया वह वहां बाजार में बेचा ग्रौर तीसरा मेरा ग्रारोप था कि इसको छिपाने के लिए ग्रन्त में जा कर डाइवर्सिफिकेशन के लिए उन्होंने विनती की। तो वह पूरा ग्राना चाहिए ग्रौर सप्लीमेंट्री पूछते समय मुझे उस के लिए मौका मिलना चाहिए।

ग्रध्यक्ष महोदय : देखिए, ग्राप हिंदी में बोलते हैं तो मैं हिन्दी में जवाब देता हूं। जहां तक इस कालिंग ग्रटेंशन का सवाल है सब से पहले यह श्री सी० पी० ए० नायडू की तरफ से ग्राया। उस को उन्होंने दे दिया जो पहले ग्राया था ग्रौर उसमें यह ऐड्रेस्ड है मिनिस्टर ग्राफ इंडस्ट्रीज को। वैसे भी ग्रगर ग्रापने प्राइम-मिनिस्टर को भेजा है तो ग्राखीर में मिनिस्टर के पास जायगा जिसका यह डिपार्टमेंट है। यह तो बात जानी पहचानी है।......

श्री मधु लिमये : इस में ताली बजाने की क्या बात है ? प्रधान मंत्री जवाब देने से भागने लगीं और आप ताली बजा रहे हैं । वह इतनी बड़ी नेता हैं तो उनको जवाब देना चाहिए ...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत सा झगड़ा इस तरफ से शुरू हो कर के फिर उधर से हो जाता और ख्वामख्वाह परेशानी चेयर को हो जाती है । तो मेरे पर भी थोड़ा रहम किया करें ।

जो दूसरी बात आप ने कही वह इस में आ जाती है । बाकी आपको पता ही है कि आफिस में यह चीज आती है....

श्री मधु लिमये : ठीक है, मैं दोष नहीं दे रहा हूं । मैं इतना ही कह रहा हूं....... (व्यवधान)....मुझे कोई एतराज नहीं है । प्रश्न पूछते समय आप इसका ख्याल रखें..। (व्यवधान)....बूटा सिंह जी, आप क्यों बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है तो आप यहां आ जाइए । अगर रूलिंग आपको ही देनी है तो आप यहां आ जाइए ।

श्री मधु लिमये से मैं कह रहा था कि अगर ऐसा था तो वह मेरे पास पहले आ जाते, इस के प्रिन्ट में जाने से पहले आ जाते तो यह ठीक हो जाता ।

श्री मधु लिमये : कोई बात नहीं । प्रश्न पूछते समय आप ख्याल रखें ।

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A AHMED): The Calling Attention Notice relates to a letter alleged to have been written by the Director-General of Technical Development to the representative of a private firm in Bombay. Immediately this matter was brought to my notice, I had it looked into. The Officer, who is alleged to have sent the letter, was away in Bangkok till the 16th August, but has since returned and has submitted a statement saying categorically that the document in question is forged and has been fabricated. The photostat copy shows that the entire letter is typewritten and only the last paragraph consisting of two lines and the initials and date are in hand-writing. The last paragraph reads as follows:—

> "I would like to finalise this decision before the 31st March. Please come with the data for discussion before 30th.
>
> B. D. K.
> 15-3-69"

On seeing this hand-written portion, the Officer concerned recollected that he had written a note in an official file on a completely different subject, which contained the above mentioned short paragraph at the end. He has stated that, above his hand-written lines, someone had put some other typed material containing a whole lot of false allegations and then taken a photostat of the same so as to make it appear that the entire letter was a genuine one. The relevant file containing the aforesaid handwritten lines was called for. It was found that certain pages from this file, including the page containing the aforesaid portion, had been removed. However, an authentic copy of the relevant noting was maintained officially by another officer and is available.

The photostat copy was also forwarded to the Central Bureau of Investigation for examining its genuineness or otherwise. The CBI referred the document to the Director, Central Forensic Laboratory. I quote his opinion regarding the photostat copy: from the report of 19th august.

> "The letter in question on visual and microscopic examination, indicates that there is a clear straight line between the typewritten text and the hand-written bottom portion of the letter. The presence of this line in the photostat copy makes it possible that perhaps the handwritten portion has been added on to the typewritten portion by pasting etc. The photostat copy, therefore,

may be of doubtful origin although the final opinion in the matter can only be given after examination of the original letter of which this document is alleged to be a true photograph."

Subsequent to the report of the 19th August, I have received another report from the C.B.I. about an hour ago. The C.B.I. have stated that it appears (I quote their words)

"(a) The photo-copy is probably a foregery. It has perhaps (श्री रवि राय : कटेगोरिकल नहीं है, परहेप्स है ।) been fabricated by cutting out the last para of the letter, which is in the hand-writing of Dr. Kalelkar, from one of his notes in an office file and pasting it below the typewritten script of the letter and then making a photo-copy of it.

(b) The note portion of the file from which the above handwritten para has been cut out is now missing.

(c) The above file, according to the evidence of officers who handled this file, and contemporaneous notes in the movement diary was submitted to Shri R. K. Gupta on 30-7-69 and from it relevant notesheets were missing when it was returned by Shri Gupta on 4-8-69. This fact was immediately brought to the notice of Shri R. K. Gupta and noting was made by the clerk concerned in the movement diary.

In view of the above facts and the strong animosity that Shri R. K. Gupta bears to Shri Kalelkar, there is reasonable suspicion that the photo-copy in question was probably prepared or was brought into being with the assistance of Shri Gupta. A definite finding can, however, be given only after the completion of the investigation."

I categorically repudiate any allegation or insinuation against any of the persons mentioned in the apparently fraudulent photostat document, including the alleged writer of the letter. I would also earnestly request the Hon'ble Members to exercise the utmost care in allowing publicity to such matters, particularly when there is serious doubt regarding the genuineness of the document in question. To assist the completion of enquiry of the CBI, however, I hope the Hon'ble Members concerned will make available the original letter also and otherwise co-operate with Government in bringing the real culprits to book.

As regards the issue of the diversification permission, I would like to state categorically that neither I nor any of the two Secretariat Officers referred to in the photostat document had dealt with this subject or issued any instructions or held any discussions with the Director-General in this regard. The Director-General had dealt with the proposal himself in consultation with one of his senior officers, and gave the permission sought, in accordance with the rules. Nor had the visit of the Secretary of the Ministry on a deputation abroad on the 21st April any bearing on the diversification case which was decided by the Director-General himself on the 31st March.

The House is aware that attempts at character assassination are on the increase and only some months ago I had to repudiate in the House a wild and malicious rumour that had been set afoot by interested parties. I would again request the Hon'ble Members to Exercise the greatest circumspection in such matters, not only when it relates to Members of the House, but particularly where officials of Government, who cannot defend themselves in the House, are sought to be involved. Unless we give our Officers adequate protection in such matters, the entire administrative machinery is likely to be seriously affected.

On completion of the CBI enquiry, which is now going on, I assure the House that such action as is called for

[Shri F. A. Ahmed]

would be taken against the persons involved.

SHRI BUTA SINGH: Shri R. K. Gupta should be hauled up. He should be prosecuted.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़): आपने यह नहीं बताया कि श्री गुप्ता के खिलाफ जिन्होंने उसको चिपकाया है, आपने क्या कार्यवाही की है। आपने इसके बारे में पढ़कर क्यों नहीं बताया ?

MR. SPEAKER: I would suggest that let there be no further questions on this.

When the hon. Member came before me and he came to my Chamber, I told him that unless I had some proof or near-about proof about the authenticity of the document, I could not admit the calling-attention-notice. So, he came forward with the photostat copy. After having heard the hon. Minister's statement, I think that we should be very cautious in such matters . . .

SHRI MADHU LIMAYE: Why are you giving your final judgment ? I strongly object.

अभी तक सी०बी०आई० ने डेफिनेट ओपीनियन नहीं दी है। उसकी डेफिनेट ओपीनियन आने के बाद कहिये, उसके पहले आपको कहने का अधिकार नहीं है...... (व्यवधान) ......

SHRI BUTA SINGH: He cannot dictate to the Chair.

MR. SPEAKER: I think for the time being, we may postpone this calling-attention-notice and wait for the report of the CBI. I shall keep it pending.

श्री मधु लिमये : उसके आने के बाद कहिये।

MR. SPEAKER: The hon. Member was very impatient. I was just going to say that myself.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि सी०बी०आई० एन्क्वायरी कर रही है, लेकिन इस के अलावा और भी बहुत से गोलमाल हैं, वे सारी चीजें आनी चाहियें।

MR. SPEAKER: He can send it to the hon. Minister.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I cannot send it to him. He himself is the culprit, and how can I send it to him? His name is there. So, how can I send it to him?

MR. SPEAKER: If the House agrees, I think we will postpone this to some other date till the inquiry is complete and the report is available.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: The Minister has charged me with relying on a fraudulent document. I have got to explain.

MR. SPEAKER: Preliminary inquiries show that it is probably forged. Pending the receipt of the final report, we should postpone this to some other day.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: No, Sir.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: No, I do not agree. The Minister has charged me. You cannot deny me my right to reply to that. You must give me a chance to make a personal explanation.

MR. SPEAKER: Let the inquiry be completed and let their report come.

श्री मधु लिमये : सी०बी०आई० की डेफिनेट ओपीनियन नहीं है, उसके आने के बाद आप कुछ कहिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह तो सारा गेंग है, कांस्पिरेसी है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री के कहने से अगर आप पोस्टपोन करेंगे तो यह गलत प्रेसिडेन्स होगा। आप हमको इसके बारे में सवाल पूछने दीजिये।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I have got the right to explain.

MR. SPEAKER: Yes.

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor): The CBI report says that there is a definite indication that it is false. Therefore, it should not be entertained any further.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I do not know why this socialist is coming in the way of the truth being known. I am sorry for him.

The Minister says it is a fraudulent document. That means there is a charge against me and I have to clear myself.

SHRI MADHU LIMAYE: Not yet.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I am placing a copy of the letter on the Table. This must be given to the members and they have a right to know what is contained in this letter—I am handing over the copy at the Table.*

MR. SPEAKER: It is already there.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I can prove that it is a genuine letter. It is not fraudulent. (*Interruption*).

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे पास फोटोस्टेट कापी है, इनके दस्तखत हैं, सेक्रेटर के दस्तखत हैं. . . . (व्यवधान)

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: We need not wait for the CBI report. I can say one thing to show that it is not fraudulent. By mistake, in my sincerity, I sent a photostat copy to the Prime Minister for inquiry. The Prime Minister has passed it on to the Industrial Development Minister. The Minister has given it to the people involved in this. So what they have done is......

SOME HON. MEMBERS: Collusion.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I suspect that they might have incorporated a line on that photostat copy and sent it to the police for getting a report saying that it is not genuine.

I have got another copy. I can give it, not to these people, because I do not trust them, but to a judicial inquiry body so that they can even send it to Scotland Yard at my cost for examination and report. I am prepared to pay the cost involved. I can give it only to a judicial authority.

There is circumstantial evidence to show one thing. The Minister has said that the words in the last paragraph are not part of the noting on the file of the DG Technical Development. I am glad they have agreed. Will any man with any common sense write on the file as if he is writing to any person?

In this letter he has written:

> "I would like to finalise this decision before the 31st March. Please come with the data for discussion before 30th.
>
> Signed B.D.K. 15-3-69"

I have read the portion which the Minister said was correct. He has written; it is written in handwriting. Can anybody write on a file like this? Can anyone with some common sense not understand it? This is the correct document. I can prove it...... (*Interruptions.*)

MR. SPEAKER: I thought the House should have another opportunity when everything can be discussed. If they do not want to take another opportunity, let them go on.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: We want a judicial enquiry. Is it a fact that after I wrote to the Prime Minister with a photostat copy on the 13th of this month, Shri R. P. Goenka of Asian Cables and Mr. K. B. Singh, General Manager were called to Delhi at the instance of some officers or the Ministers. I do not know; I cannot

---

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the paper was not treated as laid on the Table.

[Shri Chengalraya Naidu]

say—and consultations were held with them by Mr. Wanchoo, Mr. Kalelkar and Mr. K. D. N. Singh? Does this not confirm that there is complete collusion between the officers and the firm? I further understand that the officers had consultations with handwriting experts with a view to declare that the handwriting of Kalelkar on the letter was fake but when that was not possible, they decided to declare this letter as fake and pass on the blame to some junior officer to make him a scapegoat?

I ask the Minister how those very same persons who are involved in the letter can declare it a fake document? Why has not the Minister suspended those officials involved in this case? Will the Minister entrust this matter to a judicial enquiry? Is there not sufficient circumstantial evidence? Is it not a fact that the Industrial Adviser Mr. Menon brought to the notice of the Secretary and the Director General of Technical Development the black marketing indulged in by the Asian Cables and Somayya and Co. in the matter of polythene? Is it not a fact that they applied for diversification of the licence to manufacture polythene pipes to cover their black marketing activities? Is it not a fact that permission for diversification was issued on 31st March? Is it not a fact that Mr. Gupta a junior officer mentioned in that letter was transferred to another section in the same Ministry? Things are very clear and there is clear circumstantial evidence to prove that the letter was true.

In that letter they had written that Mr. Gupta would be transferred and they need not worry. They said: you pay us the money and give us the data; we shall issue diversification licence by the 31st March. What is the usual procedure? Papers go from the clerk, to the superintendent, to the higher ups. In this case the Director General of Technical Development called the file without any clerk or assistant putting it up. He issued orders giving permission for diversification. How do you say that there is nothing wrong in this? There is sufficient justification now for handing the matter over to a judicial enquiry.

I do not believe they are entangling the Minister but by their entangling the Minister by mentioning his name, these officers are trying to get out of it. Therefore, to get out of the muddle, I want the Minister to entrust this to a judicial body. This is a most important thing, and to get out of this muddle, the Minister, in his own interest, has to do this. These officers must be kept under suspension immediately.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: Order, order.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH (Parbhani): Sir, I rise to a point of order. My point of order arises out of this. The Minister has made a statement with reference to a Call Attention Motion, and the hon. Member of this House, in his right to have a personal explanation, has challenged that statement and has said that the statement made by the Minister is untrue. In the circumstances. what remains in the hands of this House to do is to refer the entire matter to the Privileges Committee, because a judicial commission can only be ordered by the Government. If the Government is not prepared to have a judicial commission, this House can refer the matter to the Privileges Committee and let the Committee go into the matter and submit its report to the House. (*Interruption*).

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: There is a question of privilege involved in this. (*Interruption*).

SHRI F. A. AHMED: Mr. Speaker, Sir, the main allegation is that the photostat copy was handed over to me and that I handed it over to my officers and it is they who have given

this reply. May I tell the hon. Member that neither the hon. Member nor anyone handed over the photostat copy to me. The copy was given by the hon. Member to the Prime Minister.

AN. HON. MEMBER: He said so.

SHRI F. A. AHMED: From her office, it has gone to the CBI. It has nothing to do so far as my Ministry is concerned. It has gone direct to the CBI. It has not come to my Ministry at all. On that basis, the CBI has been making an enquiry. I have said that the hon. Member should co-operate with the CBI in order to place all the material which is at his disposal before the CBI, and on the basis of those things, the enquiry may proceed. Now, whatever action is called for against anyone involved, that action will be taken. That is what I am saying. We do not want to conceal anyone. So, I would appeal to the hon. Member that he should place the original letter before the CBI.

The only thing that strikes me is that no one would be so foolish as to write in a letter saying "Give me Rs. 4 lakhs for doing this work." (*Interruption*). No one will write like that and say "I will take it." (*Interruption*)

MR. SPEAKER: Shri Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह साफ करना चाहता हूं कि जहां तक इस पत्र का और चार लाख का सवाल है, उस पर मैं इस वक्त अपनी कोई राय नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है कि यह मामला सी०बी०आई० के विचाराधीन है और सी०बी०आई० ने कोई निश्चित राय नहीं दी है। इसलिए मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपके सामने ऐसे सबूत रखना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि एशियन केबिल कम्पनी और औद्योगिक विकास मंत्रालय के बड़े अफसर किस तरह कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसमें कैसे भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। . . . . (**व्यवधान**) . . . .

आप लोगों के दिल में इतनी घबड़ाहट और धड़कन क्यों होने लगी है ?

13 hrs.

मैं आपके सामने एशियन केबिल्स कार्पोरेशन लि० की रपट और एकाउंट्स, 1966-67 रख रहा हूं। यह तो फोर्जरी नहीं हो सकती है ? इसमें दो आइटम्स हैं जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक है पेज 13 पर :

"RAW MATERIALS GIVEN ON LOAN

(Partly secured by deposit of Rs. 8,94,500) Rs. 841,625."

तो इनके पास जो कच्चा माल यूसर्ज लाइसेंस के ऊपर आया था यह इन्होंने लोन दिया है और कम्पनी के अकाउन्टस में दिखाया गया है कि कच्चा माल कर्ज के तौर पर दिया गया है।

अब दूसरा आइटम है 7 पेज पर। वह है बिक्री के बारे में, कुछ माल बेच दिया गया। कुछ कर्ज में दिया, कुछ बेच दिया गया

"Sales include sales of raw materials amounting to Rs. 25,23, 585. These include sales of imported raw materials of Rs. 16,75,752 being surplus and/or defective. Application for clearance and/or permission of Government in respect of these sales has been made by the Company."

यह तो एकदम डोकूमेंटरी एवीडेंस है। मैं आपकी आज्ञा से इम्पोर्ट रैड बुक से दो पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं :

"Conditions of Actual User licences

"This licence is issued subject to the condition that all items of goods imported under it shall be used only in the licence holder's factory at the address shown in the application against which the licence is issued and for the purpose for which the licence is

[Shri Madhu Limaye]

issued, or may be processed in the factory of another manufacturing unit but no portion thereof shall be sold to any other party or utilised or permitted to be used in any other manner. The goods so processed in another factory shall, however, be utilised in the manufacturing processes undertaken by the licensee. The licensee shall maintain a proper account of consumption and utilisation of the goods imported against the licence in the prescribed manner."

आगे आप यह देखिये—मिसयूज आफ एक्चुअल यूजर्स आफ लाइसेंसेज

"It has been noticed that in some cases, the actual users divert to other channels/uses the raw materials or components etc. licensed to them for use in their factories. Attention of the actual users is drawn to the condition applicable to A.U. licences, to the effect that the goods shall be utilised in the licence holder's factory only for the purpose for which they are imported, and no portion thereof shall be sold to or permitted to be utilised by any other party. Steps are taken to ensure that this condition is strictly complied with. If any licensee infringes the aforesaid condition no further assistance will be given to him for the import of goods in the category of actual users, without prejudice to any other action which may be taken against him under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 and the Imports (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955."

अब अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस पौलीथीन के बारे में यह सवाल पूछा गया है, इसके बारे में जब औद्योगिक मंत्रालय में शिकायतें आयीं कि कम्पनी इम्पोर्ट रूल्स का उल्लंघन करके यह कच्चा माल ज्यादा मंगवाती है, जरूरत से ज्यादा, और जरूरत से ज्यादा इम्पोर्ट लाइसेंस कैसे मिलता है ? क्या मुफ्त में मिलता है ? बात साफ है कि जिसमें लाखों और करोड़ों रुपयों का मुनाफा है, इस तरह के लाइसेंस जो दिये जाते हैं तो इसके पीछे जरूर भ्रष्टाचार का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय, किसने कितना लिया इसमें मैं नहीं जा रहा हूं । मेरा सवाल यह है कि क्या यह बात सही नहीं है कि जो पौलीथीन मंगवाया गया, जिसकी जरूरत 50 टन से ज्यादा नहीं थी, लेकिन मंगवाया गया 1,000 टन से अधिक और बाकी सारा माल बाजार में बेच दिया गया, या कर्जे पर दे दिया गया, और इसमें कम से कम 50 लाख, और हो सकता है कि एक करोड़ रु० तक बनाये गये हैं ।

यूजर्स लाइसेंसेज पर जो माल है उसके दूसरे इस्तेमाल के बारे में, डाइवर्सिफिकेशन की परमीशन दी जाती है । लेकिन उस बारे में कुछ नियम बने हैं, जो मैं सदन को बताना चाहता हूं । एक तो नियम यह है कि इसमें विदेशी मुद्रा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिये । यानी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिनसे विदेशी मुद्रा खत्म हो जाय । इन्होंने एक हजार टन तक मंगवाकर विदेशी मुद्रा बरबाद की ।

दूसरा नियम यह है कि अगर प्रायरिटी इंडस्ट्री के लिए डाइवर्सिफिकेशन की मांग की जाती है तब तो इजाजत दे सकते हैं । लेकिन पौलीथीन पाइप्स कोई प्रायरिटी लिस्ट में नहीं है ।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस तरह की इजाजत किसने दी और क्यों दी गयी ? इन्होंने कैटेगौरिकली कहा है कि मैंने नहीं दी है, डायरेक्टर जनरल ने दी । मान लीजिये कि यह बात सही है कि इसमें इनका हाथ नहीं है, जिस के बारे में मुझे शक है, वह बाद में साबित होगा । मान लीजिये कि डायरेक्टर जनरल ने दी तो डायरेक्टर जनरल ने नियम के अनसार दी है, ऐसा इनका

कहना है। मैं कहना चाहता हूं कि इस की जांच होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीरता से और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने डिफेक्टिव टायर्स का मामला उठाया, माननीय मसानी साहब जानते हैं, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी जानती है, मैंने सल्फर डील का मामला पी०ए०सी० में उठाया, वूल टौप्स का मामला ऐस्टीमेट्स कमेटी के सामने गया और उस समिति ने मेरी बात की पुष्टि की। इसी तरह से बैरल और ड्रम का मामला उठाया, ऐस्टीमेट्स कमेटी ने मेरी बात की ताईद की। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी जुडिशियल इनक्वायरी के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या अध्यक्ष महोदय यह पूरा मामला हमारे सदन की ऐस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के पास या और किसी स्पेशल कमेटी के पास भेजेंगे? एक एक बात को मैं साबित करूंगा।

मैं आज मंत्री महोदय को, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि क्या के० पी० गोयनका ग्रु.प के पापों पर चादर बिछाने की आपने कोशिश नहीं की? चाहे बिड़ला हों, शान्ति प्रसाद जैन हों, तालुकेदार हों, टाटा हों, मफ़तलाल हों, हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य एक-एक का मामला खोलने की कोशिश करते रहेंगे जब तक कि इस देश से पूंजीवाद का खात्मा नहीं होता है। हम चुप हो कर बैठने वाले नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय और सरकार जुडिशियल इनक्वायरी के लिए तैयार हैं पूरे मामले की। और अगर तैयार नहीं है तो जिस तरह से माननीय संजीव रेड्डी ने हमारे पांच, छः मामले सदन की समितियों को भेजे थे, और एक एक मामले की वहां पुष्टि हो गयी, और इस मामले को भी पुष्टि करने के लिये मैं तैयार हूं, उसी तरह से इस मामले को भी सदन की किसी समिति के सुपुर्द किया जाय। अगर दोनों में से एक भी काम नहीं होगा तो दुनिया समझ जायेगी कि इसमें पापी कौन है, गलत कौन है? हम हैं या सरकार है। बस मुझे इतना ही कहना है।

SHRI F. A. AHMED: I have listened with rapt attention to the hon. Member for all the general wild allegations which he has made.

SHRI MADHU LIMAYE: Wild?

SHRI F. A. AHMED: Sometimes people think of others as they themselves are. When I have made a statement.... (*Interruption*).

श्री कंवर लाल गुप्त : यही जवाब है आपका ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हां, हां, यही जवाब है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये । जब उन्होंने आपको सुना तो आप भी उनकी बात सुनिये ।

श्री मधु लिमये : मंत्री जी अगर शुद्ध हैं तो एक वाक्य में जवाब दे सकते हैं कि इनक्वायरी के लिये तैयार हैं ।

SHRI F. A. AHMED: When I have made a statement that so far as this particular matter is concerned, it was not referred to me at any stage, if the hon. Member has any evidence, I challenge him to produce that evidence . . . . (*Interruption*).

श्री मधु लिमये : यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। आपके स्टेटमेंट के आधार पर कहा है कि मान लीजिये डायरेक्टर जनरल ने यह किया। तो इनक्वायरी के लिये तैयार हो जाइये ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मंत्री जी का जवाब सुन लीजिये ।

SHRI F. A. AHMED: You said that you doubt that.

Then, not only from what he has read from the report of the Estimates Committee but even from their balance sheet report itself, it is evident that Messrs Asian Cables have been selling some of the imported articles. Therefore what the DGTD has done is—that is my information—that they have reported this matter to the Controller of Imports and Exports and the matter is under inquiry. They have reported the matter and you cannot blame the DGTD and say that when this matter was brought to their notice they had not taken any action; on the other hand, they have said that in selling it they have not taken permission from the DGTD.

श्री मधु लिमये : डाइवर्सिफ़िकेशन की परमीशन क्यों दी ?

SHRI F. A. AHMED: They have not given permission for the purpose of selling.

For the purpose of diversification may I point out that the general orders do not restrict it to the priority industry list at all. So far as the first 25 per cent of the diversification is concerned, the officer can give that permission provided for the purpose of diversification no material or component is imported and so on.

SHRI MADHU LIMAYE: Is polythene indigenous material?

SHRI F. A. AHMED: That is within the jurisdiction of the officer concerned. For that purpose, they need not refer either to the Secretary or to me. But even then if there is any allegation, I am prepared to look into it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What about you?

SHRI F. A. AHMED: Even about me, if you have any material against me, I challenge it . . . (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये : मेरा सवाल था कि क्या मंत्री महोदय निष्पक्ष न्यायिक जांच के लिये तैयार हैं ? इन की जांच से मेरा मतलब नहीं है । हां या न कहें ।

SHRI F. A. AHMED: I have said that. If any material about any irregularity, any illegality, is brought to my notice, the proper action will be taken.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मेरा साफ़ प्रश्न था । वह हां या न कहें ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, जो कसूरवार हो उस को सजा मिले । मेरा ख्याल है कि यह सीधा करप्शन का सवाल है । इस में कोई पौलिटिक्स नहीं है । इस के अन्दर एक साजिश है सेक्रेटरी की, जौइंट सेक्रेटरी की, कालेलकर की और मिनिस्टर साहब की . . .

श्री बूटा सिंह : और गुप्ता जी की ।

श्री कंवर लाल गुप्त : जहां तक मेरे रिलेशन का सवाल है मैं स्पीकर साहब, आप से प्रार्थना करूंगा कि आप उस की इनक्वायरी करें, होम मिनिस्टर करें, सी बी आई करे । अगर मेरा रिलेशन कैसा ही टेढ़ा मेढ़ा साबित हो और मैं कसूरवार हूं तो मैं सज़ा लेने को तैयार हूं लेकिन उन सदस्यों को भी सज़ा मिलनी चाहिए । उन्होंने अपने लैटर में यह कहा है :

> "My understanding with you for Rs. 4 lakhs may be confirmed and your side will take care of any payment to others direct. For my purpose, you are only to ensure that the support of Secretary and Minister is there whenever needed . . ."

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जब इतना सीरियस मामला है तो छोटे लेविल पर इसे नहीं होना चाहिए । मैं दुहराना नहीं चाहता हूं जोकि मधु लिमये जी ने कहा है कि चाहे यह लैटर मान लिया जाय कि फे

हो तो भी सरकमस्टेंशियल एविडेंस सारी ऐसी है जिस से लगता है कि यह लैटर बिल्कुल जैनुइन है। मेरा कहना है कि मैसर्स एशियन कबल्स लिमिटेड के साथ यह बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। उस के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री के पी गोइनका को अभी दम विभूषण दिलाया गया है। यह जो तीनों अफसर हैं उन के खिलाफ़ इसी एक केस में नहीं पहले से ही सी बी आई की इनक्वायरी हो रही है। राज नारायण ने राज्य सभा में जो आरोप लगाये थे उस के बारे में काफ़ी दिनों से सी बी आई की इनक्वायरी हो रही है। इस फर्म के रशियन कोलैबरेशन के बारे में जब चीफ़ कंट्रोलर इम्पोर्टस ने यह लिखा कि उसे सस्पेंड कर दिया जाय तो क्या यह सही नहीं है कि आप के सेक्रेटरी वांचू साहब ने कहा कि उस का लाइसेंस सस्पेंड मत करो उस को चलने दो और उस के साथ साथ और लाइसेंस देने दो ? इस में मेरा कहना यह है कि कालेलकर साहब के टोटल ऐसैट्स 30 लाख रुपये के हैं जोकि उन के और उन के रिश्तेदारों के नाम से प्रापरटी के हैं।

दूसरी चीज मैं आप की आज्ञा से केवल यह कहना चाहूंगा कि आखिर यह जो डाइवरसीफिकेशन हुआ वह डाइवरसीफिकेशन हुआ क्यों ? यह डाइवरसीफिकेशन ब्लैकमार्केटिंग को छिपाने के लिए हुआ। मेरे पास उन ओरिजनल लैटर की फोटोस्टैट कौपी है जिस में उन्होंने ब्लैकमार्केटिंग की हुई है..

MR. SPEAKER: You may send it to them, whatever material you have got.

श्री कंवर लाल गुप्त : केबिल्स ही उन्होंने नहीं बेचे। उन्हें यहां पर 500 टन टीटैनियम मिला जबकि रिक्वायरमेंट केवल 50 टन की ही थी। बाक़ी सारा ब्लैक मार्केट में बेचा गया। इसी तरह से अल्यूमीनियम में भी किया गया (व्यवधान) . . .

MR. SPEAKER: All sorts of allegations are being made. As the hon. Minister said, you may send it to the C.B.I.

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे क्वेश्चन तो कर लेने दीजिये। आप ने अभी कहा कि उसे मंत्री महोदय के पास भेजें। मेरा कहना है कि जब एक प्राइमाफेसी केस है और यह कोई एक केस नहीं है और भी केसेज़ हैं और मंत्री महोदय चाहें तो मेरे पास भी कई केसेज़ हैं जिन में कि इन अफसरान ने गड़बड़ की है जैसे हिन्दुस्तान इलैक्ट्रिकल कम्पनी वालों को एक दिन में ही फौरेन कोलैबरेशन मिला। ऐसी ही चीज ज्योति लिमिटेड के सिलसिले में भी की गई। इन सब केसेज़ को जल्दी फौलो अप करने के लिए लिखा हुआ है। मेरे पास फोटोस्टैट कापी है। जहां शुबहा मंत्री के ऊपर है, जहां शुबहा सेक्रेटरी के ऊपर है अथवा जहां शुबहा ज्वाएंट सेक्रेटरी के ऊपर हो कालेलकर के ऊपर हो तो इस तरह से इस में न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय स्वयं अपने इंटरैस्ट में, हमारे इंटरैस्ट में नहीं, इस मामले की जुडिशिएल इनक्वायरी करायें। अगर वह वाक़ई चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय तो या तो मंत्री महोदय इस के लिए जुडिशिएल इनक्वायरी करायें या इसे फिर पब्लिक एकाउंट्स कमेटी को सौंप दें और इस बीच में मैं चाहूंगा कि जो यह अफसरान हैं उन को सस्पेंड कर दिया जाय। यह मुहकमा प्राइम मिनिस्टर साहब स्वयं मंत्री महोदय से ले कर अपने हाथ में सम्हाल लें अन्यथा न्याय संभव नहीं हो पायेगा और यह जाहिर हो जायेगा कि मंत्री महोदय द्वारा इस पर परदा डाला जा रहा है क्योंकि आज वह विशेष राजनैतिक पावर में हैं (व्यवधान)...

MR. SPEAKER: When allegations are to be made against a Minister there is a procedure for that . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I wrote to you a letter that I wanted to raise it . . .

MR. SPEAKER: Not that.

[Mr. Speaker]

अगर कोई माननीय सदस्य किसी मिनिस्टर के खिलाफ़ कोई आरोप लगाना चाहें तो उस के लिए एक अलहदा प्रोसीज्योर है जिसको कि वह ऐडाप्ट कर सकते हैं लेकिन इस तरह से वह इनवौल्व नहीं कर सकते हैं और कॉल अटेंशन नोटिस के दौरान वह ऐसा नहीं कर सकते। उस के लिए एक अलहदा प्रोसीज्योर है।

SHRI F. A. AHMED: The only thing which Mr. Gupta has said is in reference to a letter. The genuineness of the letter is also challenged. As I pointed out, there is a typed portion and also a hand-written portion. I have not been able to understand why there should be a type-written as well as a hand-written portion. In that type-written portion it has been stated by the person against whom the allegation has been made that he wants Rs. 4 lakhs and he says, 'You look after so far as Secretary or the Minister is concerned'. I do not know how that can be regarded as a proof that I have taken something in this deal. I have not been able to appreciate that. I again challenge Mr. Gupta that if he has any material before him, he may place it before the C.B.I. which is making an investigation. (*Interruption*) Regarding the other allegations, if he has specific allegations let him come forward with those allegations. What is the use of talking like this? (*Interruption*).

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I have got photostat copies here.

MR. SPEAKER: We pass on to the next item.

13.18 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report of the C.S.I.R. for 1967, etc.

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO):

(1) (i) Annual Report (Hindi and English versions) of Scientific and Industrial Research for the year 1967 along with the Audited Accounts for the year 1966-67.

(ii) Annual Report of the Council of Scientific and Industrial Research for the year 1968 along with the Audited Accounts for the year 1967-68.

(2) A statement showing reasons for the delay in laying the above papers.

[*Placed in Library. See* No. LT-1773/69.]

Review by Government on the working of the India Tourism Development Corporation Ltd., etc.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SAROJINI MAHISHI): On behalf of Dr. Karan Singh, I beg to lay on the Table.

(1) Review by the Government on the working of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 1967-68.

(2) Annual Report of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi